

के.डी.न्यूज़

सुलतानपुर से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

UPHIN 47497

वर्ष—01 अंक 22 सुलतानपुर मंगलवार 26 नवम्बर 2024

मूल्य : दो रूपया पृष्ठ : 4

पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी दिवस की देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नयी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 116वें एपिसोड को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साथियों, आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल-कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूँ, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आस-पास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहाँ मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट जरूर मौजूद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे।



कटका बाजार में आये दिन लग रहा है भयंकर जाम, जिम्मेदार बने मौन।

सुलतानपुर— अयोध्या प्रयागराज पर स्थित कटका बाजार में आये दिन लग रहा है भयंकर जाम, जिम्मेदार बने मौन। स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम की मुख्य वजह बनी है बाजार में सड़क तक अतिक्रमण चाहे व पटरियों गुमटी हो चाहे वह सवारी गाड़ियों का बीच चौराहे से सवारी भरना, साथ ही दाद में खाज का काम कर रहा है मयांग रोड से बड़े बड़े डंपरों से कई गाड़ियों का मिट्टी ढोने का काफिला एक साथ निकलना और फिर जाम लगने पर बेतरतीब हो कर एक साथ बीच चौराहे से निकलने की होड़ लगाना। फिर



थोड़ा आगे जाने पर सेमरी मोड़ के पास बेतरतीब वाहनों का फिर से जाम लगा देना। लगभग एक हफ्ते से यह जाम द्वारिकगंज से लेकर डोडापुर बाबूगंज के पास तक लग रहा है। यही नहीं वाहनों का डबल लाइन बना कर एक ही रास्ते से निकलना। इन सब समस्याओं पर अगर पुलिस और साथ ही इस पर चलने वाले मुसाफिर ध्यान रखें तो इस जाम से मुक्ति मिल सकती है। यह भी लोगों का कहना है कि शायदी ब्याह के चल रहे कार्यक्रम से भी सड़क पर भीड़ बढ़ी है। यह भी कहना ठीक है लेकिन अगर इन चौराहों पर अतिक्रमण व कोई भी सवारी वाहन या प्राइवेट वाहन खड़े ना हो तो जाम की समस्या से बचा जा सकता है नही तो इस समस्या में अकेले पुलिस भी कुछ नहीं कर पायेगी।

सोमवार से शुरुहुआ पेंट माय टायलेट का विशेष अभियान

सुलतानपुर। स्वच्छता अभियान से जन-जन को अवगत कराने की मंशा से आज से पेंट माई टॉयलेट अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक शौचालय को रंग बिरंगे पेंटिंग के जरिए सजाया जाएगा। पेंटिंग में स्वच्छ भारत मिशन के स्लोगन और स्वच्छता से होने वाले लाभ के चित्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्वच्छता का जीवन पर होने वाला सकारात्मक प्रभाव पेंटिंग के जरिए दर्शाया जाएगा। अभियान के तहत सभी शौचालयों की साफ सफाई दिन में दो बार कराई जाएगी। शौचालय पर टोल फ्री नंबर 1533 दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने दी।

कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का दावा होगी लापरवाह जिम्मेदार के ऊपर बड़ी कार्रवाई

घघसरा गोरखपुर। सहजनवा तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा व पाली उर्वा पर, के अगल-बगल नगर पंचायत सहजनवा व घघसरा में वर्षों से धड़ल्ले से संचालित हो रहा अवैध रूप से प्राइवेट अस्पताल डायग्नोस्टिक सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर जिसको लेकर प्रमुखता से साक्ष्य के साथ लगातार इन यम रूपी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ प्रतिष्ठित अखबार व इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में प्रमुखता खबरों के माध्यम से यम रूपी फर्जी स्वास्थ्य की हर एक कमियों को प्रकाशित किया गया

जिस संदर्भ में लगातार जिले पर बैठे एडिशनल डायरेक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लगातार जानकारी लेने के बाद सिर्फ जांच और कार्रवाई के नाम पर आश्वासन ही मिलता रहा वहीं कुछ दिन पहले घघसरा में फर्जी प्राइवेट नेशनल अस्पताल को सील किया गया था। लेकिन अधीक्षक डॉक्टर सतीश सिंह, स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के मदद से सील तालों को भी तोड़ा गया और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ टाल मटोल ही किया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पूर्व मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के द्वारा फर्जी प्राइवेट अस्पताल

प्रा० यशवंतराव केलकर की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी - मुख्यमंत्री



एजेंसी। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन (22 से 24 नवम्बर, 2024) के अवसर पर प्रधानाध्यक्ष यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कर्ण बिहारी युवाओं के जीवन में कोशल, शिक्षा तथा रोजगार के मा

बिटिया सुभाषिनी का जन्मदिन मनाया गया पोद्दार कैंसर अस्पताल में

गोरखपुर। दिग्विजयनाथ पी.जी. कॉलेज, गोरखपुर के सहायक आचार्य डॉ. पवन कुमार पाण्डेय ने आज अपनी बेटिया सुभाषिनी पाण्डेय को जन्मदिन एक विशेष और प्रेरणादायक तरीके से मनाया। उन्होंने इस अवसर पर गोरखपुर के पोद्दार कैंसर अस्पताल के मरीजों के साथ समय बिताया और उनके साथ खुशियां साझा की। इस अनोखे आयोजन ने समाज सेवा और सामाजिक दायित्व को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। डॉ. पवन कुमार पाण्डेय ने बताया कि उनके लिए यह दिन केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने

के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट भी लगाया गया था इतना ही नहीं फर्जी तरीके से संचालित होने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थानों के बाद सिर्फ जांच और कार्रवाई के नाम पर आश्वासन ही मिलता रहा वहीं कुछ दिन पहले घघसरा में फर्जी प्राइवेट नेशनल अस्पताल को सील किया गया था। लेकिन अधीक्षक डॉक्टर सतीश सिंह, स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के मदद से सील तालों को भी तोड़ा गया और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ टाल मटोल ही किया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पूर्व मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के द्वारा फर्जी प्राइवेट अस्पताल

कब्जा हटवाने जेसीबी लेकर गए प्रशासन को लौटना पड़ा

दुकानदारों ने कहा कि 32 वर्ष से मजीठिया ने बेची थी भूमि, उसी भूमि पर है काबिज

चौरीचौरा गोरखपुर। बांसगांव संदेश। चौरीचौरा तहसील क्षेत्र के संस्था चौराहे पर सोमवार की शाम को तहसील प्रशासन व पुलिस टीम चौधरी भंडिकल स्टोर के पीछे का कब्जा हटवाने के लिए जेसीबी के साथ पहुंची। इसकी सूचना पर सैकड़ों की संख्या में दुकानदार पहुंच गए और जमकर विरोध किया। विरोध को देखकर टीम को वापस लौटना पड़ा। संस्था उद्योग समूह के लिक्विडेटर द्वारा शिकायत की गई थी कि चौधरी भंडिकल स्टोर पर सैकड़ों रुप में भूमि को कब्जा किया जा रहा है। शिकायत पर एसडीएम प्रशांत वर्मा ने अतिक्रमण हटवाने के लिए टीम गठित किया था। लेखपाल चंचल मिश्रा, विप्लव सिंह व अन्य लेखपालों के साथ पुलिस की टीम जेसीबी लेकर पहुंची तो चौधरी भंडिकल स्टोर के मालिक विवेक कुमार चौधरी ने बताया कि कोई नया कब्जा नहीं है। पुराना



कब्जा है। मिल मालिकान ने 32 वर्ष पूर्व 1992 में पैसा लेकर बिना कागज का भूमि बेच दिया था। बिना किसी नोटिस के कब्जा हटवाने के लिए टीम आई थी। मिल के बंद होने के बाद संस्था चौराहे पर सैकड़ों दुकानदार अपनी दुकान खोलकर रेजी रेटी चला रहे हैं। पूर्ण के स्टेट मैनेजर ने पैसा लेकर लोगों को दुकानों को पीछे तक कब्जा करवाया था। अब इसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना था कि उनके दुकान का मामला दीवानी न्यायालय में लंबित है। ऐसे में जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटवाने के लिए टीम का आना न्यायालय का उल्लंघन है। उनका कहना है कि न्यायालय में चल रहे केस का अभिलेख भी टीम को दिया गया है। मामले को लेकर दुकानदारों ने विद्यार्थक ई सरवन निषाद से भी वार्ता किया है। कि न्यायिक न्यायालय को अपने आवस्य पर वार्ता स्टोर के मालिक विवेक कुमार चौधरी ने बताया कि कोई नया कब्जा नहीं है। पुराना

चौरी चौरा के ग्राम-भैसही नरेश में लगा एक-दिवसीय श्रमिक चौपाल

चौरी चौरा, गोरखपुर। चौरी चौरा के विकास खंड ब्रह्मपुर के ग्राम-भैसही नरेश के पंचायत भवन पर दातोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के क्षेत्रीय निदेशालय गोरखपुर के द्वारा एक दिवसीय श्रमिक चौपाल सामाजिक संस्था श्रवण कुमार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में लगाया गया। जिसमें ग्राम पंचायत-भैसही नरेश के पंचायत भवन में भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री ई श्रम योगी, ई श्रम कार्ड, नेशनल करियर सर्विस, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी), अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को बताया गया एवं सैकड़ों लोगों का सरकार के विभिन्न योजनाओं में निःशुल्क पंजीकरण किया गया। कार्यक्रम में सतीश सिंह (ग्राम प्रधान) विश्वजीत जायसवाल (संस्था सचिव) अभय सिंह (पंचायत सहायक) डॉ. घनश्याम लाल (वरिष्ठ योग प्रशिक्षक) उदित नारायण (सामाजिक कार्यकर्ता) ओमप्रकाश (सफाई कर्मी) इत्यादि पदाधिकारी एवं आम जनता मौजूद थी।

12 पंचायत सहायकों का रोका गया एक दिन का वेतन



पिपरीली गोरखपुर। पिपरीली ब्लाक मुख्यालय के मुख्य सभागार में सभी पंचायत सहायकों की जिरों पॉर्वटी अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन कर एडीओ पंचायत अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आज पंचायत सभी पंचायत सहायकों की एक बैठक आयोजित की

गोरखपुर में चौकी इंचार्ज को बंधक बनाकर पीटा

गोरखपुर। सिकरीगंज में जमीनी विवाद के मामले में गांव में पहुंचे एक चौकी इंचार्ज को बंधक बनाकर पीटने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सिकरीगंज थाना क्षेत्र दुधरा चौकी अंतर्गत राजन यादव अपने घर गोरखपुर से गांव पर आएं थे। यहां राम सिंह के पुत्र सरवन यादव और राम यादव ने मिलकर राजन यादव को बुरी तरह रविवार सुबह पीटा। 100 नंबर पर सूचना देने के कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर अपने घर भेज दिया। दोपहर करीब 2 बजे दोनों पक्षों के बीच पिर विवाद हो गया। दोनों पक्ष आपस में टकराने लगे और ईट पत्थर भी चलने लगे। कुछ देर बाद दुधरा चौकी इंचार्ज राकेश कुमार और विनीत सिंह मौके पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज द्वारा लोगों को समाझाया बुझाया जा रहा था। इसी दौरान सरवन कुमार ने घर की औरतों को आगे कर दिया और सरवन की तरफ से चौकी इंचार्ज पर हमला कर दिया। चौकी इंचार्ज को बुरी तरह से पीटा गया। इस दौरान दोनों पक्ष भी आपस में भिड़े और दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आईं। देर शाम को पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार, क्षेत्राधिकारी खजनी, थानाध्यक्ष बेलघाट और थानाध्यक्ष सिकरीगंज मौके पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज से मारपीट करने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है।

के.डी.न्यूज

(हिन्दी दैनिक)



योगेंद्र योगी । आयोग की इस सिफारिश को अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। आयोग के इस प्रस्ताव में प्रदेश में कानून–व्यवस्था की मौजूदा हालत जि्क्र नहीं है। आयोग ने यह भी नहीं बताया कि सिफारिश में किए गए प्रावधान ही क्या महिलाओं के साथ होने वाले अपराध

कों के लिए जिम्मेदार हैं । देश के संवैधानिक आयोग नखदंतविहीन हैं। ऐसे में भी आयोग के कर्ताधर्ता नेताओं की तरह व्यवहार करके आयोग की गरिमा को कम करने के साथ ही उपहास का पात्र बनते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग ने इसी तरह का कृत्य करके अपनी महत्ता को कम करने का काम किया है। आयोग ने योगी सरकार को एक सिफारिश की। इसमें प्रदेश में पुरुष टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़ों के माप लेने पर रोक लगाने, कोचिंग सेंट्रों में सीसीटीवी कैमरे, जिम में महिला ट्रेनर लगाने का जि्क्र किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आयोग ने यह प्रस्ताव भी भेजा है। आयोग का यह कृत्य दर्शाता है कि आयोग मूल उद्श्यों से भटक कर राजनीतिक पैतरेबाजी करने में जुटा है। आयोग को उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने से कोई

सम्पादकीय

सुर्खियां बटोरने के लिए यूपी के महिला आयोग का पैतरा

सरोकार नहीं है। आयोग की इस सिफारिश को अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। आयोग के इस प्रस्ताव में प्रदेश में कानून–व्यवस्था की मौजूदा हालत जि्क्र नहीं है। आयोग ने यह भी नहीं बताया कि सिफारिश में किए गए प्रावधान ही क्या महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। आयोग ने अपराधों के बाद पुलिस कार्रवाई के तौर–तरीकों पर एक लाइन भी नहीं कही। बालिकाओं के शैक्षणिक स्थलों के पास छेड़छाड़ की घटनाएं रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की स्थायी तैनाती पर आयोग चुप रहा। महिला आयोग ने यह भी नहीं बताया कि प्रदेश में इतनी संख्या में प्रशिक्षित महिलाएं का इंतजाम कैसेा होगा। क्या सरकार इसके लिए महिलाओं के प्रशिक्षण का इंतजाम करने में सक्षम है। प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार के लिए महिलाओं को ऋण और स्थान इत्यादि की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर आयोग की सिफारिश में कोई जि्क्र नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की धिंता करने वाला उत्तर प्रदेश का महिला आयोग यह भूल

गया कि प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है। यात्रियों से ठसाठस भरे वाहनों में महिलाओं को बेहद मुश्कलों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए प्रदेश में अलग से परिवहन की व्यवस्था नहीं है। आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं को भारी मशकत करनी पड़ती है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं से छेड़छाड़ की बात आम है। महिला हिताों की पैरवी करने वाले महिला आयोग की निगाह यहां तक नहीं पहुंची। इसी तरह महिलाओं की बीमारियों से और प्रसूती की हालत से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सकों और अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है।

आयोग ने पुलिस थानों में महिलाओं की पर्याप्त संख्या और महिला पुलिस थानों की जरूरत पर जोर नहीं दिया। महिलाओं के लिए आज भी पुलिस थानों में जाकर शिकायत दर्ज कराना आसान नहीं है। पुलिसकर्मों पीडि्धत महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश

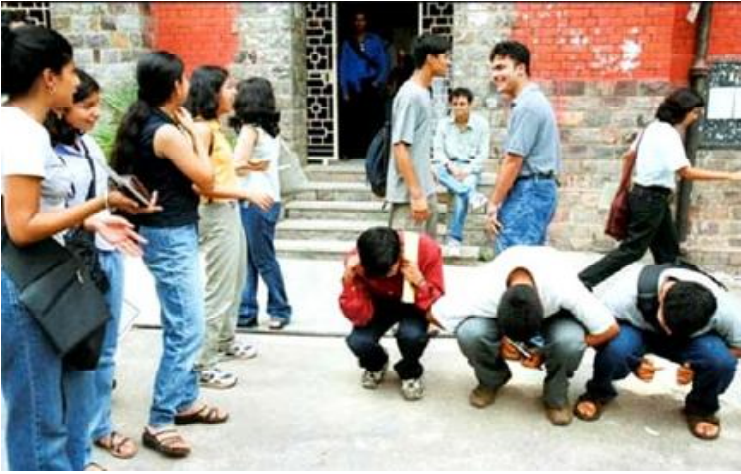
में योगी सरकार ने माफिया और गैंगस्टरों को धूल चटाने में कसर बाकी नहीं रखी। प्रदेश से लगभग सभी बड़े माफिया और गैंगस्टर या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेलों में बंद हैं। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि आम लोगों के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। पुलिस में भ्रष्टाचार और भेदभाव की घटनाएं आम हैं। आयोग ने इन तमाम मुद्दों को नजरंदाज कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में महिलाओं की नियुक्ति की पैरवी करने वाला आयोग राज्य में महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर सक्रिय कार्रवाई नहीं कर सका। हाथरस और उन्नाव कांड इसका उदाहरण है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आयोग ने कोई भूमिका नहीं निभाई। 14 सितंबर, 2020 को हाथरस में एक दलित युवती के साथ चार पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार किया। इसी तरह 4 जून, 2017 को उन्नाव में 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इसमें लड़की की

मौत हो गई। ऐसे मुद्दों पर आयोग कोई ठोस सुझाव राज्य सरकार को नहीं दे सका। भारत में बाल मजदूरों का सबसे ज्यादा संख्या 5 राज्यों में है। सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश में 21.5 फीसदी यानी 21.80 लाख और बिहार में 10.7 फीसदी यानी 10.9 लाख बाल मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरों की संख्या 21.7 लाख है। यह यूपी की कुल आबादी का 21 फीसदी है। हालांकि यह मुद्दा सीधा महिला आयोग के तहत नहीं आता, फिर कोई महिला अपने कलेजे के टुकड़े से मजदूरी कैसे करवा सकता है। महिला आयोग ने कभी इस पर विचार नहीं किया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों (जैसे बलात्कार, हत्या, अहरण, बलात्कार के बाद हत्या और सामूहिक बलात्कार) की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर रहा। इसमें 65,743 ऐसे मामले दर्ज किए गए। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बागडोर संभाली थी, तो उन्होंने महिलाओं के सार्वजनिक उत्पीडन को रोकने के लिए प्ष्टी–रोमियो स्वर्वॉडफ का गठन किया था।

बाद में उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के नाम पर गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 बनाया, जिसे लव–जेहाद विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। अपराध के आंकड़े इन बात के गवाह हैं कि इन कानूनों के बन जाने के बाद भी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसकी राज्य महिला आयोग ने कभी समीक्षा नहीं की। गौरतलब है आयोग को सिर्फ नोटिस देकर बुलाने का अधिकार है, कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

अपने इस अधिकार के लिए भी आयोग ने कभी आवाज बुलंद नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि आयोग का महिलाओं की सुरक्षा की सिफारिश का दावा खोखला है। धरातल की हालत से दूर ऐसी सिफारिश सिर्फ सुर्खियां बटोरने से ज्यादा कुछ नहीं है।



पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद देश के अनेक उच्च शिक्षा संस्थान इससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। रैगिंग एक ऐसा शब्द है जो हर साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वलास शुरू होते ही सुनवाई देने लगता है। दुनियाभर में हर साल लाखों स्टूडेंट्स को इसका सामना करना पड़ता है। रैगिंग को दुनिया में अलग–अलग नामों से पहचाना जाता है। इसको हेजिंग, फेगिंग, बुलिंग, प्लेजिंग और हॉर्स प्लेजिंग के नामों से भी जाना जाता है। रैगिंग कई कारणों से हो सकती है, जैसे आक्की त्वचा, नस्ल, धर्म, जाति, प्रजातीयता, जेंडर, यौनिक रुझान, रूप–रंग, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, आपकी बोली, जन्म स्थान, गृह स्थान या आर्थिक प्रृष्ठभूमि। रैगिंग अलग–अलग रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी अन्य छात्र को उसके काम करने के लिए धूसं दिखाता है या किसी छात्र को कॉलेज समारोह जैसी परिसर की गतिविधियों से बाहर रखा जाता है, तो उसे रैगिंग माना जाता है। मानसिक बोट, शारीरिक दुर्व्यवहार, भेदभाव, शैक्षणिक गतिविधि में व्यवधान आदि सहित छात्रों के खिलाफ रैगिंग के विभिन्न रूपों को कानून दंडित करता है।90 के दशक में भारत में रैगिंग ने विकराल रूप ले लिया था। इसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में रैगिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही यूजीसी ने भी रैगिंग के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। रैगिंग पर कुछ शिक्षण संस्थानों के अपने नियम हैं। उदाहरण के लिए, ऑल इंडिया कारॉसिल फॉर टैकिनकल एजुकेशन के पास रैगिंग पर दिशा–निर्देशों की अपनी एक नियमावली है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग को प्रतिबधित करने व रोकने के लिहाज से विभिन्न राज्यों ने कानून पारित किए हैं, जो केवल उन संबंधित राज्यों में ही लागू होते हैं। एक सर्वे के अनुसार तो देश के अधिकांश कॉलेजों में करीब 40 फीसदी छात्रों को किसी न किसी रूप मेंरैगिंग या सीनियर छात्रोंद्वारा ब्मकाने का सामना करना पड़ता है। अभिभावक अपने बच्चों को उनका भविष्य संवावने के लिए शिक्षा संस्थानों में भेजते हैं। मगर यह शिक्षा संस्थान रैगिंग के कारण उनके बच्चे के लिए मौत के कारण बनते हैं। (हिफ़ी)

रैगिंग के नाम पर छात्रों के जीवन से खिलवाड़?

आखिर यह रैगिंग कब तक छात्रों के जीवन पर भारी पड़ेगी? गुजरात के एक एमबीबीएस छात्र की रैगिंग के दौरान की गयी अमानवीयता से मौत ने हर अभिभावक को भीतर तक झकझोर दिया है कि आखिर उनके बच्चों के साथ कालेज कैम्पस में क्या–क्या हो रहा है? यह बेहद गंभीर दु:खद, निंदनीय और शर्मनाक बात है कि देश में तमाम कड़े कानूनों और सरकारों की कठोर नीतियों के बावजूद शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। देश के किसी न किसी कॉलेज और विश्वविद्यालयों से रैगिंग की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लागू किया है, मगर देश में रैगिंग के बढ़ते मामलों से यह कानून मजाक बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर देश में रैगिंग को कई घटनाएं सामने आयी हैं। ताजा जानकारम में गुजरात और तमिलनाडु में रैगिंग के मामले सामने आए हैं। दु:खद बात है कि गुजरात के पाटन में रैगिंग के कारण एमबीबीएस के छात्र की मौत हो गई है। शुरूआती जांच में सामने आया है कि 18 साल के जूनियर छात्र को लगातार तीन घंटे तक प्रताड़ित किया गया था। होस्टल में सीनियर्स द्वारा रैगिंग के दौरान कथित तौर पर उसे तीन घंटे तक खड़ा रखा गया। धारपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र अनिल मेधानिया को

तीन घंटे तक जबरन नाचने और खड़े रहने को मजबूर किया गया। इस कारण छात्र बेहद घबरा कर बेहोश गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अनिल की मौत के बाद उसके परिवार ने वरिष्ठ छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया और दावा किया कि इसी वजह से उसकी मौत हुई। धारपुर मेडिकल कॉलेज के डीन हार्दिक शाह ने पुष्टि की कि अनिल बेहोश हो गया था। उन्होंने जानकारी दी है कि पूछताछ के दौरान छात्रों ने खुलासा किया कि घटना के समय वास्तव में परिव्यात्मक सत्र चल रहा था। कॉलेज ने कार्रवाई करते हुए 15 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रैगिंग के नाम पर अमानवीयता दरिंदगी व दुराचार की वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला जारी है। 18 फरवरी 2024 को केरल के एक कालेज के छात्रावास के टायलेट के छत से 20 साल के छात्र का शव लटका मिला। छात्र वीवीएसपी पशुपालन द्वितीय वर्ष का छात्र था जांच के बाद पता चला कि उसके साथ दो दिन पहले रैगिंग की गई और यौन शोषण किया गया था। 6 अप्रैल 2024 को ही दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल के नाबालिग छात्र के स्कूल पार्ट में सीनियर छात्रों ने डंडा घुसा दिया। छात्र को आईसीयू में भर्ती कराया गया। 14 अक्टूबर

22 को आइ आइटी खड़गपुर में छात्र फैजान का आंशिक रूप से सड़ चुका शव मिला था। आरोप है कि उसके साथ सीनियर छात्रों ने लंबे समय तक रैगिंग के नाम पर अमानवीयता दरिंदगी की। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया। 9 अगस्त 2023 को एक 17 साल के नाबालिग छात्र की छात्रावास की बालकनी से गिरने से मौत हो गई थी। जांच में रैगिंग के नाम पर यौन शोषण और अमानवीयता का मामला सामने आया और एक दर्जन से अधिक छात्रों पर पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया। उधर, तेलंगाना में एक टीचर ने मामूली सी स्टूडेंट के साथ मारपीट की और नाई की दुकान पर ले जाकर उसके बाल मुडवा दिए। इस घटना की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत दी गई है। पिछले सप्ताह ही खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने अपनी जान दे दी थी। यह घटना 27 जुलाई को थी। यह इस पर कई सच सामने आये हैं। नोएडा के एक निजी विश्वविद्यालय के छात्रावास में कनिष्ठ विद्यार्थियों की पिटाई की गई थी। विचित्र है कि यह मामला एक महीने तब तक दबा रहा, जब तक कि एक पीडित छात्र ने धाने में

शिकायत नहीं दर्ज कराई।यह तो सिर्फ चंद बानगी भर है देश के सभी राज्यों के सभी उच्च शिक्षण संस्थान रैगिंग की बीमारी से ग्रस्त हैं और प्रतिभावान छात्र–छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ करने का सिलसिला जारी है।

ये वारदातें बताती हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध सख्त नियमों और अदालतों के साफ दिशा– निर्देशों के बावजूद नए विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने या उनके खिलाफ हिंसा की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सख्त नियम–कायदे के बावजूद रैगिंग करने वाले युवाओं के भीतर कानून का भी न कोई डर है, न उन्हें अपने भविष्य को कोई चिंता है। निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों पर रौब जमाना या किसी को प्रताड़ित करना यह बताता है कि कुछ युवाओं में दमन की कुठित मानसिकता काम करती रहती है। यही कारण है कि रैगिंग रोकने के लिए अलग–अलग राज्य सरकारों ने रैगिंग को लेकर अपने नियम–कानून बनाए हैं। इनमें कारावास से लेकर अर्थ दंड तक के सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर देखा जाए तो रैगिंग की समस्या उच्च शिक्षा जगत से जुड़ी अत्यंत संवेदनशील, सामाजिक समस्या है, जिससे उच्च शिक्षा जगत को

रेखा का बेबाक अंदाज, शादी से प्यार तक

रेखा भारतीय सिनेमा की एक लीजेंड हैं, जो साउथ सिनेमा के महान एक्टर जेमिनी गणेशन की बेटी हैं। बचपन में कमाने की मजबूरी ने उन्हें वक्त से पहले परिपक्व बना दिया। एकट्रेस की जिंदगी में फिर ऐसा वक्त आया, जब उन्होंने अपनी फितरत के खिलाफ जाकर अरेंज मैरिज की। एकट्रेस की जिंदगी में फिर ऐसी अनहोनी ने दस्तक दी कि वे सुकून पाने की चाह में खुद में सिमट कर रह गईं। रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और विनोद मेहरा जैसे सितारों के साथ जुड़ा, मगर उन्होंने बिजनेसमेंन मुकेश अग्रवाल से अरेंज मैरिज की। कहते हैं कि रेखा को मुकेश अग्रवाल बहुत प्यार करते थे, मगर दोनों बिल्कुल अलग शख्सियत थे। उनके बीच मतभेद की खबरें आईं, फिर अचानक मुकेश अग्रवाल के निधन ने लोगों को चौंका दिया। सिमी ग्रेवाल ने अपने चेट शो ‘रान्दिव् विद सिमी ग्रेवाल’ में उनकी मुकेश अग्रवाल के साथ शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा, तो रेखा बोलीं, ‘हम कैसे मिले यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि मैंने उस शादी से क्या सीखा।’ रेखा पति के निधन के बाद शांत हो गई थीं। जब सिमी ग्रेवाल ने सवाल किया, तो उन्होंने खुद को शर्मीला इंसान बताया। वे ट्रेजेडी से उबरने में सफल रहीं। सिमी ग्रेवाल ने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना कि रेखा नशा करती हैं। वे साफ–सुथरी हैं। इस पर रेखा ने कहा, ‘मुझे नशे की लत रही है। मैंने ड्रग्स लिए हैं। मैं अपवित्र हूं और वासना से भरी हूं, लेकिन पूछो किससे– जिंदगी से।’ रेखा का बेबाक अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है। वे अमिताभ बच्चन के लिए खुलकर अपना प्यार जाहिर करती रहीं।

रेखा–अमिताभ आखिरी बार 1981 की फिल्म ‘सिलसिला’ में नजर आए थे, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी लाइमलाइट में आ गई थी। अमिताभ बच्चन के लिए रेखा का बेबाक बयान आज भी लोगों का ध्यान खींचता है। रेखा ने 1984 में ‘फिल्मफेयर’ को दिए इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के ‘प्यार से इनकार’ पर अपना रिएक्शन दिया था और उनके लिए अपने एहसास बयां किए थे। रेखा ने अमिताभ की तरफदारी करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी और फैमिली की इमेज खराब होने से बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन यह भी माना कि वे एक–दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा था, ‘अगर मेरे सामने उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया होता, तो मैं बहुत निराश होती।’



मंदाकिनी के झरने वाले दृश्य ने मचाया था तहलका

साल 1985 में राज कपूर एक ऐसी फिल्म लेकर आए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले उनकी फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ में जीतन अमान ने अपनी बोल्डनेस से दर्शकों को चौंका दिया था। इसी तरह साल 1985 में आई ‘राम तेरी गंगा मैली’ में राज कपूर ने मंदाकिनी को इस कदर बोल्ड अंदाज में पेश किया था कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। राज कपूर ने मंदाकिनी को ‘राम तेरी गंगा मैली’ में पूरी फिल्म में ही ऐसी वेशभूषा में पेश किया था कि लोगों ने इस फिल्म के कई सीन पर सवाल उठाए थे। खासतौर पर फिल्म का गाना तुझे बुलाए ये मेरी बांहें। आजा रे। गंगा ये तेरी हैं फिर कैसेी देरी हैआजा रे इस गाने के सामने आते ही हंगामा मच गया था। इस गाने में झरने में ट्रांसपेरेंट कपड़ों में नहाती मंदाकिनी ने तो तहलका मचा दिया था। फिल्म में झरने के नीचे बोल्ड सीन देकर मंदाकिनी ने चारों ओर तहलका मचा दिया था। इस सीन के बाद राजकपूर को सेंसर बोर्ड को जवाब तक देना पड़ गया था। लेकिन इस फिल्म से राज कपूर के करिश्म को भी नई दिशा मिली थी। कहा जाता है कि जब जीतन अमान ने फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ में झरने के नीचे झीने–झीने कपड़ें मेंनहाते हुए बेबाक पोज दिए तो हलचल ही मच गई थी। इसी तरह ‘राम तेरी गंगा मैली’ फिल्म में भी ये आईकॉनिक झरना सीन को लेने का आईडिया राज कपूर को मिला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर पहले पदिमनी कोल्हपुरे को कार्ट करना चाहते थे लेकिन वह इस तरह के सीन नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। (हिफ़ी)

